पी–एच. डी.

# उपाधि हेतु प्रस्तावित

शोध–प्रारूप

## सामाजिक विज्ञान संकाय (अर्थशास्त्र)

–: शोध शीर्षक :–

# बिहार के समावेशी विकास में कृषि नीति की भूमिका : दरभंगा जिला के संदर्भ में एक अध्ययन

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,

कामेश्वरनगर, दरभंगा


शोध–निर्देशक
डॉ. अम्बरीष कुमार झा
*अध्यक्ष*
*विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग*
*ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,*
*दरभंगा*

Khushboo Kumari
शोधार्थी
**खुशबू कुमारी**
**विषयः अर्थशास्त्र**
**पैट रॉल नं०–E2205005**
**PAT-2021-22**

# पी-एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तावित शोध-प्रारूप

## सामाजिक विज्ञान संकाय (अर्थशास्त्र)

## ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा।

**1. शोध समस्या का शीर्षक:**

**बिहार के समावेशी विकास में कृषि नीति की भूमिका : दरभंगा जिला के संदर्भ में एक अध्ययन**

**2. शोध समस्या का विवरण**

समावेशी विकास का अर्थ विकास के उस पैमाने से है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हो सके। जो गरीबी को कम करने में मदद कर सके। इसमें अवसर की समानता प्रदान करना और शिक्षा व कौशल विकास के द्वारा लोगों को सशक्त करना शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई सारी योजनाओं की शुरूआत की है जो समाज के हाशिए के लोगों को मुख्यधारा में लाने में मदद करेगा और उन तक तीव्र आर्थिक विकास का फायदा पहुंचाएगा। दूसरे शब्दों में ऐसा विकास जो न केवल नए आर्थिक अवसरों को पैदा करे, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सृजित ऐसे अवसरों की समान पहुंच को सुनिश्चित भी करे। समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाओं यानी आवास, भोजन, पेयजल, शिक्षा, कौशल, विकास, स्वास्थ्य के साथ–साथ एक गरिमामय जीवन जीने के लिए आजीविका के साधनों की उपलब्धता भी हासिल कराना है। वस्तुपरक दृष्टि से समावेशी विकास उस स्थिति को इंगित करता है जहां सकल घरेलू उत्पाद की उच्च संवृद्धि दर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की उच्च संवृद्धि दर में परिलक्षित हो तथा आय एवं धन के वितरण की असमानताओं में कमी आए।

Signature 18/03/24

भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं आर्थिक नियोजन के 75 वर्ष पश्चात् भी कृषि क्षेत्र का सर्वोपरि महत्त्व है। आज भी भारत में व्यवसाय और जीविका की दृष्टि से 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। वर्तमान में भी कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड बना हुआ है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के समावेशी विकास संबंधी अधिकांश परियोजनाएँ और

Khushboo Kumari

कार्यक्रम कृषि अर्थव्यवस्था के कायापलट करने के उद्देश्य से निर्मित और क्रियान्वित की जाती है। इसका मुख्य कारण है कि आज भी जनसंख्या का दो तिहाई भाग कृषि पर निर्भर है और यदि उनका समावेशी विकास करना है तो कृषि को न केवल आधुनिक और विकसित करना होगा बल्कि कृषि करने वाले को प्रोत्साहित करना होगा।

समावेशी विकास की अवधारणा पहले–पहल ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में प्रस्तुत की गई थी जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने और अवसर की समानता लाने की बात कही गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में इस पर और भी जोर दिया गया जिसमें गरीबी को कम करने, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार और आजीविका के अवसर प्रदान करने जैसी बातों पर खास जोर दिया गया। सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं में इस समावेशी विकास पर विशेष बल दिया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 का तो सारा प्रयास एक प्रकार से त्वरित, समावेशी और सतत् विकास के लक्ष्य हासिल करने पर था। केन्द्र तथा राज्य स्तर पर लोगों की गरीबी दूर करने हेतु अनेक कार्यक्रम बने, परन्तु उचित अनुश्रवण के अभाव में इन कार्यक्रमों से आशानुरूप परिणाम नहीं मिले। जो योजनाएं केन्द्र तथा राज्यों के संयुक्त वित्त पोषण से संचालित की जानी थीं, वे भी कई राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने या फिर निहित राजनीतिक स्वार्थों की वजह से कार्यान्वित नहीं की जा सकीं। समावेशी विकास ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के संतुलित विकास पर निर्भर करता है। इसे समावेशी विकास की पहली शर्त के रूप में भी देखा जा सकता है।

वर्तमान में कृषि रोड मैप के जरिये कृषि को बढ़ावा देने और कृषि के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिपरक रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधनों का सृजन किया जा रहा है ताकि समावेशी विकास हो सके। वास्तविकता यह है कि भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं है विशेष कर बिहार जहां कृषि क्षेत्र से इतर वैकल्पिक रोजगार के साधन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों, क्योंकि यहाँ कोई कल कारखाने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। बिहार में सरकार को कृषि में अभिनव प्रयोगों के साथ उत्पादन में बढ़ोतरी सहित नकदी फसलों पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा

मिल सके। इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं के साथ जिला स्तर पर कार्यरत् कृषि अनुसंधान संस्थाओं की मदद से किसानों से सम्पर्क कर कृषि उपज बढ़ाने की दिशा में पहल करने के साथ कृषक के समक्ष आने वाली दिक्कतों का समाधान भी खोजने होंगे, तभी कृषि समावेशी विकास का इंजन बन सकती है।

समावेशी विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए बिहार में कृषि आधारित कई योजनाओं की शुरूआत की गई है जो समाज के हाशिए के लोगों को मुख्यधारा में लाने में मदद कर रही है। उनका तीव्रगति से आर्थिक विकास हो रहा है। कृषि सिंचाई योजना और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कृषक समुदाय को बड़े पैमाने पर मदद कर रही है, जो उनके सामाजिक–आर्थिक खुशहाली का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है। कृषि अर्थव्यवस्था समावेशी विकास के एक विराट ध्येय के साथ आगे बढ़ रही है और यह नागरिकों के बीच अवसर और हैसियत की समानता प्रदान करने का कार्य कर रही है। सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करके समावेशी विकास को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रही थी परन्तु उसमें सफलता नहीं मिली। नेशनल सैंपल सर्वे संगठन के वर्ष 2003 में किए गए किसानों की स्थिति और वर्ष 2013 में खेतिहर परिवारों की स्थिति के सर्वे के अनुसार कृषि देश में लगभग आधे श्रम बल को रोजगार देती है, लेकिन प्रति व्यक्ति सबसे कम उत्पादन करती है और इसलिए गरीबी के सबसे उच्चतम स्तर से जुड़ी हुई है, इससे यह साफ है कि अगर भारत में समावेशी विकास होगा, तो इसकी शुरुआत कृषि क्षेत्र से करनी होगी। वर्ष 2003 से 2013 के बीच वास्तविक अर्थों में समग्र आय में 1.34 गुना की वृद्धि हुई। हालांकि जिन किसानों के पास ज्यादा भूमि है, उनकी आय में तेज वृद्धि हुई, जबकि कम भूमि वाले किसानों की आय में वृद्धि सुस्त रही। जिन खेतिहर परिवारों के पास दस एकड़ से ज्यादा भूमि थी, उनकी आय दोगुनी हो गई। असल में न्यूनतम एक हेक्टेयर भूमि वाले खेतिहर परिवारों की आय में कम से कम 1.5 गुना की वृद्धि हुई। छोटे किसानों की आय में सबसे कम वृद्धि हुई, 0.4 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत किसानों की आय में मुश्किल से 1.1 गुना की वृद्धि हुई। सामान्य रूप से छोटे भूस्वामियों की आय वृद्धि सुस्त रही। जहां तक भूस्वामित्व की बात है, तो समावेशी विकास के विपरीत–एक प्रतिगामी विकास की स्थिति देखने को मिली।

Khushboo Kumari

बिहार में आय में ठहराव और कई प्रमुख राज्यों में आय स्रोतों में विविधता की कमी समावेशी विकास और आय असमानता पर सीधे सवाल खड़ा करती है। वर्ष 2013 में खेती ने कुल आय का करीब आधा (49 फीसदी) प्रदान किया और आधी से ज्यादा आय कई महत्त्वपूर्ण राज्यों–पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में केंद्रित रही। जबकि मजदूरी महत्त्वपूर्ण थी और जिसने 2013 में करीब 31 फीसदी आय प्रदान की। खेती से आय की तुलना में मजदूरी बहुत सुस्त गति से बढ़ रही थी। सबसे कम महत्त्वपूर्ण आय स्रोत गैर कृषि व्यवसाय (आठ फीसदी) था। ध्यान देने वाली बात है कि गैर–कृषि व्यवसाय तीन राज्यों–केरल, प. बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी आय में दस फीसदी से ज्यादा का योगदान नहीं कर रहा है। खेती से निम्न आय स्तर और निरंतर कृषि भूमि के विखंडन को देखते हुए समावेशी विकास की संभावना संभव नहीं है। वर्ष 2010–11 में औसत कृषि भूमि का आकार 1.15 हेक्टेयर था। पिछले चालीस वर्षों में, जबसे कृषि जनगणना शुरू हुई है, कृषि भूमि का औसत आकार घटकर आधा रह गया है और सीमांत किसानों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है। कृषि भूमि के निरंतर विखंडन का आय उत्पादन और कृषि क्षेत्र में आय असमानता, दोनों पर गंभीर असर पड़ा है। बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं को साकार करने, कर्ज तक पहुंचने या निर्वाह खेती के विरोध में बाजारोन्मुख खेती के दौर में छोटे किसानों की समस्याओं को देखते हुए इसकी बहुत संभावना है कि उत्पादकता में वृद्धि के लिए तैयार की जाने वाली अधिकांश, नीतियां बड़े किसानों को लाभान्वित करती हैं। छोटे और सीमांत किसानों को ऐसी नीति से कम लाभ होगा। अगर किसानों की आय को दोगुना करना संभव भी हो गया, तो यह निश्चित रूप से बड़े किसानों की आय वृद्धि पर आधारित होगा। भूमि के निरंतर विखंडन से निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास संभव नहीं होने वाला है। बिहार में हरित आवरण को 9 से बढ़ाकर 15 फीसदी करने का लक्ष्य तय किया गया है तथा 2021–22 के उपलब्ध आकड़ों के आधार पर हरित आवरण 13 फीसदी हो चुका है। लेकिन 15 फीसदी लाने के लिए कृषि अनुसंधान को प्रयोगशाला से खेतों तक ले जाना होगा। प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता और उसके संरक्षण को ध्यान में रखकर अनुसंधान करना होगा क्योंकि समावेशी विकास कृषि के विकास के आधार पर ही सम्भव है। बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ

Khushboo Kumari

की 76 फीसदी आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। खेती के विकास के बिना प्रदेश का समावेशी विकास सम्भव नहीं है। प्रदेष में समावेशी विकास के मकसद से राज्य सरकार कृषि के क्षेत्र में इन्द्रधनुषी क्रान्ति के मकसद से कृषि रोड मैप के आधार पर कार्य कर रही है। इसके लिए 250 आबादी वाले प्रत्येक बसावट को पक्की सड़क से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है ताकि किसान अपने उत्पादों को आसानी से बाजार तक ले जा सकें। भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए नये गोदामों का निर्माण तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य भी किया जा रहा है। कृषि के विकास के लिए तकनीकी विकास आवश्यक है, इसके लिए कृ षि के क्षेत्र में अनुसंधान आवश्यक है। अनुसंधान के लिये उन्नत कृषि संस्थानों की आवश्यकता होती है, इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य के द्वितीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसी विश्वविद्यालय से अंगीभूत कोसी तथा सीमांचल क्षेत्र में तीन कृषि महाविद्यालयों की स्थापना सहरसा, पूर्णियाँ एवं किशनगंज में की गई है। इतना ही नहीं सुखाड़ से निबटने के लिए राज्य सरकार द्वारा डीजल अनुदान हेतु निर्धारित राशि को 25 रूपये प्रति लीटर से बढाकर 30 रूपये प्रति लीटर कर दिया है तथा तीन पटवन से बढाकर पाँच पटवन कर दिया है। देश में दूसरे हरित क्रांति की सम्भावना उत्तर–पूर्व के राज्यों में है। बिहार में भी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि की उन्नति से ही हरित क्रांति सम्भव हो सकेगी। बिहार सरकार समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कृषि रोड मैप के जरिए छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तुत अध्ययन में बिहार के समावेशी विकास में कृषि की भूमिका को स्पष्ट किया जायेगा।

**3. पूर्व अध्ययनों की समीक्षा :**

समावेशी विकास एवं कृषि नीति जैसे मुद्दों पर कई विद्वानों ने अपने–अपने विचार व्यक्त किए है। इस विषय पर स्रोत सामग्री की उपलब्धता है:–

**विनोद बहल (2019)** ने अपले लेख "समावेशी विकास के माध्यम से ग्रामीण बदलाव में लिखा है कि समावेशी विकास के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली कृषि के उत्थान के लिए सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 187233 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। यह किसानों को उनकी

Khushboo Kumari

फसल का एक बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए, ई–राष्ट्रीय कृषि बाजार पर खर्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2016–17 में फसल कवरेज क्षेत्र के लक्ष्य में 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर 2017–18 में 40 प्रतिशत और 2018–19 में 50 प्रतिशत फसल क्षेत्र को शामिल किया गया है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, तकनीक का उपयोग करके, 50,000 ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण कार्यक्रमों उपक्रमों द्वारा और 2017–18 में दीर्घकालिक सिंचाई कोष में 40,000 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत पांच साल में हर क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि कृषि क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़े और समावेशी विकास को बल प्रदान हो सके।

**इन्दिरा मिश्रा (2012)** ने अपने लेख "समावेशी विकास में उल्लेख किया है कि भारत सरकार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–11) में एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य सामने रखा गया है कि हमारा विकास समावेशी हो। संभवतः योजना बनाने वालों का ध्यान पहले के 'ट्रिकल डाउन' अर्थात् कुछ न कुछ लाभ अमीर–गरीब, सबको दिलाने की पहली पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के विपरीत, सबको लाभान्वित करने की ओर गया हो। किंतु यह बात तो उदारीकरण आदि की नीति के चलते, सबको स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को योजना से लाभान्वित किया जाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी तक हम एक उद्योग प्रधान देश नहीं बन पाए है। हमारी 62 प्रतिशत जनता कृषि संबंधी व्यवसाय में लगी हुई है, और इस सेक्टर से सकल घरेलू उत्पाद को 22 प्रतिशत योगदान मिलता है। भूमि और एक विशाल जनसंख्या हमारी ताकतें भी है। उद्योगों का अनन्त विस्तार एक आदर्श स्थिति भी नहीं है। आखिर उद्योग–भूमि का एक हिस्सा पूरी तरह से हथिया लेते हैं, प्राकृतिक साधनों, जैसे जल, कोयला, विद्युत का भरपूर उपयोग करते हैं, वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं, सड़कों की दुर्दशा करते हैं। अतः उनका विस्तार जितना नियोजित हो, उतना अच्छा है। लेकिन दूसरी ओर कृषि से जुड़ी एक विपरीत परिस्थिति यह है कि बिहार जैसे इक–फसली इलाके में धान कटने के बाद दिसम्बर से जून तक लोग बेरोजगार रहते हैं। नतीजतन समावेशी विकास की अवधारणा का विकास नहीं हो पाता है। इसके लिए कृषि विकास कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सालों भर उपजाये जाने वाले फसलों की जानकारी देनी होगी

Khushboo Kumari

साथ ही उन्हें सब्सिडी भी देना होगा तभी जाकर उनका आर्थिक स्तर बढ़ेगा और समावेशी विकास का सपना सच हो सकेगा।

**बी.एल. सोनेकर एवं भूमिराज पटेल (2013)** ने अपने आलेख "कृषि एवं ग्रामीण विकास में स्पष्ट किया है कि कृषि को राज्य का सबसे बड़ा रोजगार दिलाने वाला नियोक्ता कहा जा सकता है जिसकी सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 4 प्रतिशत है जो देश में समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम है। किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है ग्यारहवी पंचवर्षी योजना में कृषि के क्षेत्र में 4 प्रतिशत विकास का लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। कृषि के लिए महत्त्वपूर्ण है सिंचाई के लिए पानी, इसके प्रबंधन में पानी के इस्तेमाल के समय और गुणवत्ता में सुधार लाना होगा साथ ही उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा मिट्टी के परीक्षण और मिट्टी में पोषक तत्त्व बढ़ाने के उपायों पर भी ध्यान देना होगा ताकि लाखों ग्रामीण गरीब कृषकों के लिए आय और रोजगार के अवसर का सृजन हो सके। कृषि विकास करना समावेशी विकास नीति एक प्रमुख घटक है तथा इस संबंध में कुछ प्रगति हुई है। कृषि एक राज्य विषय है इसलिए केन्द्र को नीतियों और कार्यनीतियों में तालमेल लाने के लिए राज्यों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करना होगा। कृषि में समग्र रूप से निवेश जो वर्ष 2002–03 में कम होकर कृषि में जीडीपी का 10 प्रतिशत से भी कम हो गया था, इसमें पर्याप्त रूप से की गई है और आजकल यह निवेश कृषि में जीडीपी से भी अधिक है। कृषि में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में निवेश के ऊंचे स्तर के बेहतर परिणाम हो सके हैं। जरूरत है तो किसानों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली को चुस्त बनाने की। साथ ही संस्थागत फ्रेम एंजेसियों को जमीनी स्तर पर कार्य करने की। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने समावेशी विकास में कृषि की भूमिका को स्पष्ट किया है।

**4. शोध का उद्देश्य :**

***प्रस्तावित शोध निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित होगा:–***

- कृषि और समावेशी विकास की अवधारणा को स्पष्ट करना।
- समावेशी विकास के अन्तर्गत कृषकों की आय एवं रोजगार को बढ़ाये जाने वाले प्रयास का विश्लेषण करना।
- समावेशी विकास के अन्तर्गत कृषि प्रसार कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना।

Khushboo Kumari

❖ बिहार सरकार द्वारा समावेशी विकास हेतु कृषि उत्पादन की क्षमता के विकास में कृषि नीति को स्पष्ट करना।

**5. शोध का महत्त्व :**

कृषि को देश एवं राज्य का सबसे बड़ा रोजगार दिलाने वाला नियोक्ता कहा जा सकता है, जिसकी सकल घरेलू उत्पाद में बहुत अधिक योगदान है, किन्तु यह धीरे–धीरे कम होता जा रहा है। वर्ष 1950–51 में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 55.40 प्रतिशत था, जो 2021–22 में घट कर 14.6 प्रतिशत रह गया है, जो देश में समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम है, किन्तु इसे दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में 4 प्रतिशत विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। कृषि के विकास से न केवल ग्रामीण क्षेत्र की आय में सुधार होगा बल्कि समावेशी विकास के सपनों को साकार किया जा सकेगा। जाहिर है समावेशी विकास के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ–साथ अन्य कई क्षेत्रों पर काम करना होगा, ताकि लोगों की आय में वृद्धि हो सके और समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अतः प्रस्तुत शोध का शीर्षक **''बिहार के समावेशी विकास में कृषि नीति की भूमिका : दरभंगा जिला के संदर्भ में एक अध्ययन''** वर्तमान समय में सामयिक, प्रासंगिक एवं महत्त्वपूर्ण है।

**6. शोध की परिकल्पना**

***प्रस्तावित शोध निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर आधारित होगा:–***

❖ कृषि क्षेत्र में विकास करके ही समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

❖ समावेशी विकास के लिए कृषक एवं कृषक मजूदरों के आय को बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

❖ कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियाँ भारत के 6.40 लाख से अधिक गाँवों में रह रही 70 प्रतिशत आबादी के आय का प्रमुख स्रोत है।

❖ कृषि का विकास समावेशी विकास का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है।

❖ बिहार सरकार के कृषि नीति का लक्ष्य जैविक खेती, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, समावेशी विकास के लिए सदाबहार तकनीक पर जोर देना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जा सके।

Khushboo Kumari

**9. प्रस्तावित शोध कार्य योजना :**

***प्रस्तावित शोध कार्य को निम्न अध्यायों के अंतर्गत संपन्न किया जाएगाः—***

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम अध्याय | : | परिचय |
| द्वितीय अध्याय | : | साहित्यिक समीक्षा |
| तृतीय अध्याय | : | शोध प्रविधि |
| चतुर्थ अध्याय | : | समावेशी विकास में कृषि की भूमिका |
| पंचम् अध्याय | : | समावेशी विकास हेतु सरकार की कृषि नीति |
| षष्ठम् अध्याय | : | निष्कर्ष एवं सुझाव |
| | | संदर्भ ग्रन्थ—सूची |

**7. अध्ययन क्षेत्र :**

प्रस्तावित शोध कार्य को सम्पादित करने हेतु अध्ययन क्षेत्र के रूप में दरभंगा जिला का चयन किया जाएगा। इस जिला के अंतर्गत कुल 18 प्रखण्ड हैं तथा कुल जनसंख्या 39,37,385 है, जिसमें 20,59,949 पुरूष एवं 18,77,436 महिलाओं की जनसंख्या है। दरभंगा जिला की कुल साक्षारता दर 56.56 प्रतिशत हैं, जिसमें पुरूष साक्षारता दर 66.83 प्रतिशत हैं तथा महिला साक्षारता दर 45.24 प्रतिशत हैं। यहाँ की क्षेत्रीय भाषा मैथिली है, इसके अतिरिक्त उर्दू एवं हिन्दी भाषी लोग भी इस जिले में निवास करते हैं।

**8. अध्ययन विधि :**

प्रस्तावित शोध कार्य विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित होगा, जिसके द्वारा शोध से संबंधित बातों एवं आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। प्राथमिक स्रोत के लिए साक्षात्कार के आधार पर विश्वसनीय तथ्यों का संकलन किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया जाएगा। आवश्यकतानुसार प्रश्नावली का भी उपयोग किया जाएगा। द्वितीयक आँकड़ों के संग्रहण हेतु मुख्य रूप से शोध कार्य से संबंधित प्रकाशित पुस्तकें, इंटरनेट, विभिन्न प्रकार के दैनिक समाचार पत्रों, सरकारी प्रतिवेदन, नीति–निर्धारण पत्रों, कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें एवं पत्रिकाओं की मदद ली जाएगी।

**9. प्रस्तावित शोध कार्य योजना :**

***प्रस्तावित शोध कार्य को निम्न अध्यायों के अंतर्गत संपन्न किया जाएगा:–***

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम अध्याय | : | परिचय |
| द्वितीय अध्याय | : | अध्ययन क्षेत्र का सामान्य परिचय |
| तृतीय अध्याय | : | समावेशी विकास की उभरती प्रवृत्तियाँ |
| चतुर्थ अध्याय | : | समावेशी विकास में कृषि की भूमिका |
| पंचम् अध्याय | : | समावेशी विकास हेतु सरकार की कृषि नीति |
| षष्ठम् अध्याय | : | निष्कर्ष एवं सुझाव |
| | | संदर्भ ग्रन्थ–सूची |

**10. संदर्भ ग्रन्थ–सूची**


1. बहल, विनोद (2019) समावेशी विकास के माध्यम से ग्रामीण बदलाव, पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।


Khushboo Kumari

2. मिश्रा, इन्दिरा मिश्रा (2012) समावेशी विकास, देशबन्धु, 10 अगस्त, उत्तर–प्रदेश।
3. सोनेकर, बी.एल. एवं पटेल, भूमिराज (2013) कृषि एवं ग्रामीण विकास, रिसर्च जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटिज एण्ड सोशल साइंस, भो0–4, नं0 1।
4. शर्मा, देवेन्द्र (1994) गैट एंड इंडिया : द पॉलिटिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, साउथ एशिया।
5. कुमारी, पूनम (2013), समावेशी विकास, सुशासन एवं कृषि की भूमिका, योजना हिन्दी, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. फड़िया, कुलदीप (2011), कृषि द्वारा समावेशी विकास के माध्यम से सामाजिक बदलाव, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली की अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका।
7. मौर्या, नूतन (2014), समावेशी विकास की अवधारणा, योजना हिन्दी मासिक, नई दिल्ली।
8. प्रथम कृषि रोड मैप (2008–2012),
9. द्वितीय कृषि रोड मैप (2012–2017),
10. तृतीय कृषि रोड मैप (2017–2022),
11. आर्थिक सर्वेक्षण (2021–2022), बिहार सरकार
12. आर्थिक सर्वेक्षण (2021–2022), भारत सरकार
13. वार्षिक प्रतिवेदन, कृषि विभाग, बिहार सरकार, 2021–22,
14. शाह, सी.एच.(2019), एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इण्डिया : पॉलिसी एण्ड प्रॉब्लमस, बॉम्बे।

18/03/24

शोध–निर्देशक
डॉ. अम्बरीष कुमार झा
*अध्यक्ष*
*विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग*
*ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा*

Khushboo Kumari
शोधार्थी
खुशबू कुमारी
*विषयः अर्थशास्त्र*
*पैट रॉल नं०–E2205005*
*PAT-2021-22*